भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 323

जिसका उत्तर मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

ऑटो मिशन पॉलिसी

323. श्री जैदेव गल्ला:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की 2016-2026 की ऑटो मिशन पॉलिसी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है क्योंकि वर्ष 2026 तक वाहनों की संख्या वर्तमान 3.3 मिलियन से बढ़कर 13.4 मिलियन हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की ऑटोमिशन पॉलिसी में विभिन्न पहलुओं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, अवसंरचना, ईंधन दक्षता इत्यादि को बढ़ावा देने को शामिल करने की योजना है; और

(ड़.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ड़.):

सरकारी विभाग जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शामिल है, सहित अन्य अंशधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के साथ संयुक्त रूप से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 (एएमपी 2026) को अंतिम रूप दे दिया है:-

i) भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का चालक बनने के लिए बढ़ावा देना।

ii) भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को "कुशल भारत" कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाना।

iii) देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा और वहनीयता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी परिवहन, दोनों विकल्पों के माध्यम से सुरक्षित, कुशल और आरामदायक परिवहन सुनिश्चित करना।

iv) भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के निवल निर्यात में कई गुना वृद्धि करने का प्रयास करना।

v) उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी विनियमनों के लिए विस्तृत और स्थायी नीति व्यवस्था को बढ़ावा देना।

एएमपी 2026 भारत में ऑटोमोटिव पारि-तंत्र के क्रमिक विकास के पथ को परिभाषित करने का प्रयास करता है जिसमें वे विशिष्ट विनियमन और नीतियां शामिल हैं जो ऑटोमोटिव वाहनों, कलपुर्जों और सेवाओं के अनुसंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, विनिर्माण, आयात/निर्यात, बिक्री, प्रयोग, मरम्मत तथा रिसाइकलिंग को प्रशासित करती हैं। इसमें नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और संबंधित अवसंरचना तथा नवीन ईंधन कुशलता विनियमन भी शामिल हैं।

*****